www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 122 | जौनपुर मंगलवार, 16 दिसम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में एससी–एसटी और महिला अफसरों को प्राथमिकता दें सरकारें

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि प्रमुख पदों पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) अधिकारियों को नामित करने को प्राथमिकता दें। केंद्र ने यह निर्देश महिलाओं और एससी–एसटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कवायद के तहत जारी किया है।

कार्मिक मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र

कार्मिक मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि केवल ऐसे अधिकारियों के नाम भेजें जिन्हें दो वर्षों तक पदोन्नति के आधार पर मूल विभाग में वापस बुलाने की संभावना न हो। केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत पदों पर तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पदों पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है।

मंत्री पंकजा मुंडे के पीए अनंत गरजे गिरफ्तार

मुंबई, एजेसी। पंकजा मुंडे की निजी सहायक अनंत गर्जे की पत्नी की आत्महत्या की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने महाराष्ट्र मंत्री के सहायक को हिरासत में ले लिया है। गर्जे को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें आगे की जांच के लिए औपचारिक रूप से एसआईटी को सौंप दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में मामले की जांच के लिए पुलिस उपायुक्त (जोन 4) रागासुधा आर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। इसमें आठ अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। गर्जे की 28 वर्षीय पत्नी डॉ. गौरी पाल्वे, जो मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में दंत चिकित्सक के रूप में कार्यरत थीं, ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। पिछले महीने, पाल्वे के पिता की शिकायत के आधार पर गर्जे को गिरफ्तार किया गया और वर्ली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। दंपति ने इसी साल फरवरी में शादी की थी। पुलिस के अनुसार, पाल्वे का शव मध्य मुंबई स्थित उनके फ्लैट में मिला था। पाल्वे के परिवार का आरोप है कि गर्जे का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था और पाल्वे ने उन्हें फोन पर बात करते हुए भी पकड़ा था। परिवार का दावा है कि इसी बात को लेकर दंपति के बीच झगड़ा हुआ था और गर्जे ने कथित तौर पर पाल्वे को धमकी भी दी थी कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है।

भाजपा ने बंगाल के लिए बदली रणनीति बूथ, वोट अंतर और डाटा पर नया दांव

कोलकाता, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति को नए सिरे से आकार दे रही है। पार्टी इस बार बड़े कार्यक्रमों और हाई–प्रोफाइल राजनीति की जगह डाटा आधारित विश्लेषण, बूथ स्तर की तैयारी और वोट मार्जिन पर फोकस कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक यह रणनीति 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों व 2021 के विधानसभा चुनावों के नतीजों और वोट अंतर (मार्जिन) के गहन अध्ययन पर आधारित है। इसका उद्देश्य उन विधानसभा क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है, जहां भाजपा पहले जीत चुकी है या कड़ी टक्कर देती रही है।

50 सीटों को भाजपा ने रखा गणना से बाहर

पार्टी का मानना है कि राज्य में करीब 50 अल्पसंख्यक बहुल सीटें ऐसी हैं, जो संगठनात्मक और सामाजिक कारणों से श्संरचनात्मक रूप से कठिनश हैं। इन सीटों को पार्टी ने अपनी मुख्य चुनावी गणना से अलग रखा है। ये ऐसी सीटें हैं, जहां बूथ एजेंट तैनात करना, संगठनात्मक उपस्थिति बनाए रखना और स्थानीय नेटवर्क का मुकाबला करना लगातार चुनौतियां पेश करता है। पार्टी ने ऐसी सीटों को अपने मुख्य चुनावी गणित से बाहर रखने का फैसला किया है।

पहले से मजबूत और नई सीटों पर पार्टी का फोकस

भाजपा का तर्क है कि जब इन श्मुश्किलश सीटों को अलग कर दिया जाता है, तो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता छोटा और स्पष्ट हो जाता है। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य के मुताबिक बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वे टीएमसी के कुशासन से तंग आ चुके हैं। हम नई सीटों पर और उन क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां हम पहले जीत चुके हैं या पिछले कुछ चुनावों में स्थिर वोट शेयर बनाए रखा है।

बीजेपी हेडक्वार्टर में नितिन नबीन ने संभाली कार्य कारी अध्यक्ष की कमान, शाह–नड्डा भी रहे मौजूद

नई दिल्ली, एजेसी। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। राजधानी में भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, रवि शंकर प्रसाद और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई नेता पार्टी कार्यालय में उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। 45 वर्षीय नितिन नबीन भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बिहार से पांच बार विधायक रह चुके नबीन वर्तमान में राज्य के सड़क निर्माण मंत्री हैं और इससे पहले शहरी विकास एवं आवास एवं विधि विभाग जैसे विभागों का कार्यभार संभाल चुके हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र नबीन के पास प्रशासनिक अनुभव के साथ–साथ पार्टी के भीतर एक लंबा संगठनात्मक करियर भी है। वे आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले एएनआई से बात करते हुए नबीन ने बिहार और अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और राष्ट्रीय स्तर पर इस पद तक पहुंचने का श्रेय उनके आशीर्वाद को दिया। उन्होंने कहा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से ही यह संभव हो पा रहा है। नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन को भी स्वीकार किया।

हर जरूरतमंद की सेवा ही सरकार का लक्ष्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ''हर जरूरतमंद की सेवा करना'' है। योगी आदित्यनाथ ने यहां 'जनता दर्शन' के दौरान यह बात कही। 'जनता दर्शन' के दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए प्रत्येक फरियादी से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और सभी के प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त एवं उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। एक बयान के अनुसार, 'जनता दर्शन' में प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के एक सिपाही ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत कराया जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए मामले के उचित निस्तारण का निर्देश दिया। शाहजहांपुर से आए एक किसान ने धान खरीद केंद्रों पर लापरवाही की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, ''सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।'' मुख्यमंत्री ने शाहजहांपुर के जिलाधिकारी को खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। प्रयागराज से भी कुछ फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित मामलों में प्रयागराज के जिला एवं पुलिस प्रशासन को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''हर जरूरतमंद की सेवा ही सरकार का लक्ष्य है। सरकार पहले दिन से ही जनता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साढ़े आठ वर्षों से सरकार जनता की समस्याएं सुनने और उनके समाधान के लिए नियमित रूप से कार्य कर रही है।

इंडिगो उड़ान रद्दीकरण मामले में सुप्रीम इनकार, याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की दी सलाह

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा सैकड़ों उड़ानें रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा से कहा कि वह अपनी शिकायतें लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जाएं, क्योंकि वहां पहले से ही इसी तरह का मामला चल रहा है। मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली के बेंच ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले से ही इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा है। इसलिए याचिकाकर्ता वहीं अपनी बात रखें। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाईकोर्ट में शिकायतों का समाधान नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इस दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि नागर विमानन

महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को हो रही परेशानियों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। यह समिति उड़ानें रद्द होने के कारणों और उससे यात्रियों पर पड़ रहे असर की समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट के संज्ञान में है, तो फिलहाल वह इस पर सीधे सुनवाई नहीं करेगा। बता दें कि इससे पहले 10 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से पैदा हुए संकट पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस वजह से लाखों यात्री फंस गए और दूसरी एयरलाइंस ने मनमाने दाम वसूले। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार यात्रियों को मदद और रिफंड दिलाने के निर्देश दे। दूसरी ओर सुनवाई के दौरान इंडिगो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 5 दिसंबर को एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। यह समिति उड़ानें रद्द होने के कारणों और यात्रियों को हो रही परेशानियों की जांच करेगी।

मुंबई की 1000 एकड़ जमीन पर 50 हजार घर बनेंगे - गोयल

मुंबई, एजेंसी। मुंबई के दहिसर इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का हाई–फ्रीक्वेंसी रडार, जो अभी दहिसर में लगा है, उसे अब गोराई में शिफ्ट किया जाएगा। इससे दहिसर में सैकड़ों एकड़ जमीन खाली होगी, जहां किफायती (अफोर्डेबल) हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकेंगे। यह फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, एएआई और अन्य संबंधित विभागों की बैठक के बाद लिया गया। इस बात की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने दी। उन्होंन बताया कि रडार को शिफ्ट करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी, ताकि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू हो सके। जमीनों पर बनने वाले घर को लेकर केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि अगले पांच साल में

करीब 50,000 घर बनाए या फिर पुराने घरों का पुनर्विकास किया जाएगा। इससे लोगों को पक्के घर, बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला कई वर्षों की कोशिशों और केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से संभव हो पाया है। इससे दहिसर की पहचान अब आखिरी उपनगर के बजाय तेजी से विकसित होते क्षेत्र के रूप में होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू ने आगे कहा कि रडार हटने से दहिसर में करीब 1,000 एकड़ जमीन (6 किलोमीटर क्षेत्र में) हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए उपलब्ध होगी। इससे दहिसर के लोगों का अपने घर का सपना पूरा होगा और यह इलाका आसान और बेहतर जीवन का केंद्र बनेगा। बता दें कि दहिसर और जुहू में लगे रडार की वजह से इमारतों की ऊंचाई पर रोक लगी हुई थी। इससे आस–पास के कई शहरी विकास परियोजनाएं अटकी हुई थीं और लाखों लोग जर्जर इमारतों में रहने को मजबूर थे। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने दहिसर और जुहू दोनों जगहों से रडार हटाने का फैसला किया है। दहिसर का रडार गोराई शिफ्ट होगा और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, साथ ही केंद्र सरकार को बिना किसी कीमत के जमीन भी दी जाएगी।

एस. जयशंकर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को इजराइल का दौरा करेंगे

नई दिल्ली, एजेसी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर मंगलवार को इजराइल पहुंचेंगे, जहां वह देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जयशंकर अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आइजेक हर्जोग व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष गिदोन सार के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। एक सूत्र ने 'पीटीआई–भाषा' को बताया, चर्चा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होगी ताकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जा सके। उनकी यात्रा से कुछ दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदी से बातचीत की थी जिस दौरान दोनों नेता बहुत जल्द मिलने पर सहमत हुए। पर्यटन मंत्री हाइम काट्ज, अर्थव्यवस्था व उद्योग मंत्री नीर बरकत, कृषि व खाद्य सुरक्षा मंत्री अवी डिक्टर और वित्त मंत्री बेजालेएल स्मोट्रिच इस साल पहले भारत गए थे। यह दौरे इसलिए हुए क्योंकि भारत और उनके देश के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है और दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्मोट्रिच की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए और फिर पिछले महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की इजराइल यात्रा के दौरान एक संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए गए, जो आगे चल कर एफटीए का आधार बनेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले असम के मुख्यमंत्री

असम, एजेसी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। एक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में असम के आर्थिक विकास, अवसंरचना विकास और जन कल्याणकारी पहलों से संबंधित कई विषयों पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा का मुख्य बिंदु असम की विकास गति को और तेज करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को मजबूत करना था। मुख्यमंत्री ने असम के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने में निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और राज्य के लोगों की समग्र प्रगति और कल्याण के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बाद में, पूर्व ट्विटर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने लिखा, ष्आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हमने असम के विकास और हमारी जनता के कल्याण से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मैंने हमारी विकास यात्रा में उनके निरंतर समर्थन के लिए माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। इससे पहले रविवार को, मुख्यमंत्री शर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। उपराष्ट्रपति के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान, मुख्यमंत्री शर्मा ने राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति को असम आने और राज्य के परिवर्तन और हालिया विकास प्रगति को देखने के लिए औपचारिक निमंत्रण भी दिया। एक विज्ञप्ति के अनुसार, उपराष्ट्रपति ने इस भाव की सराहना की और 30 मिनट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की।

उच्चायुक्त को बुलाने पर भारत का सख्त जवाब, कहा-आपसी सम्मान के आधार पर आगे बढ़ें रिश्ते

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से लगाए गए आरोपों पर सख्त और स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि उसने अपनी धरती का इस्तेमाल कभी भी किसी पड़ोसी देश के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया है। भारत ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश अपने यहां कानून–व्यवस्था मजबूत करे, ताकि आम चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पूरे हो सकें। भारत का कहना है कि आपसी सम्मान और सहयोग के आधार पर ही दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं और क्षेत्र में स्थिरता बनी रह सकती है। मामला तब गरमाया, जब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बुलाकर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से दिए गए बयानों पर गंभीर चिंता जताई। अंतरिम सरकार ने अवामी लीग के कुछ नेताओं के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए आरोप लगाया कि भारत में रह रहे नेता बांग्लादेश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और 12 फरवरी को होने वाले चुनावों में बाधा डालना चाहते हैं। उच्चायुक्त को बुलाए जाने के कुछ घंटों बाद भारत ने आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी कर इन आरोपों को खारिज कर दिया।

भारत का सख्त संदेश

विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन का दुरुपयोग नहीं होने देता। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अपेक्षा जताई कि वह कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए। भारत का मानना है कि चुनावी माहौल में शांति और सुरक्षा सबसे जरूरी है, ताकि आम लोग बिना डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। भारत ने दोहराया कि रिश्ते टकराव नहीं, बल्कि संवाद और सहयोग से मजबूत होते हैं।

चुनावों पर भारत की स्थिति

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों के पक्ष में रहा है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार इस दिशा में जरूरी इंतजाम करेगी। भारत का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी, तभी दोनों देशों के बीच विश्वास और साझेदारी और गहरी होगी। भारत ने यह भी संकेत दिया कि शांतिपूर्ण चुनाव पूरे क्षेत्र के हित में हैं।

शेख हसीना और प्रत्यर्पण का मुद्दा

गौरतलब है कि पिछले साल बांग्लादेश में हिंसक छात्र आंदोलनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि सभी मुद्दों को आपसी समझ और कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए।

संपादकीय

आर्थिक विकास के लिए सहयोगात्मक संबंध जरूरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय धान पर टैरिफ लगाने की परोक्ष धमकी देकर भारत को डराने की फिर कोशिश की है, पर तथ्य इस बात के गवाह हैं कि ट्रंप प्रशासन स्वयं डरा हुआ है। पचास प्रतिशत टैरिफ का ट्रंप कार्ड 'जोकर' साबित हो चुका है। इसका क्रेडिट काफी हद तक भारतीय उद्योगपतियों को जाता है, जो दुर्भाग्य से अपने ही देश में विपक्ष के हमलों का शिकार हो रहे हैं। मौजूदा विश्व अर्थव्यवस्था में हर देश अपने उद्योगपतियों को मूल्यवान समझता है। याद कीजिए लगभग तीन दशक पहले गेट यानी जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ एंड ट्रेड के जरिए भारत समेत विकासशील देशों पर दुनिया भर में टैरिफ कम करने का दबाव डाला गया था। आज अमेरिका खुद उसी टैरिफ की आड़ ले रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून का उल्लंघन हो रहा है। घरेलू मोर्चे पर एलन मस्क जैसे बड़े उद्योगपति ट्रंप से मुंह मोड़ चुके हैं। ट्रंप के दबाव के बावजूद हाल में माइक्रोसाफ्ट और गूगल ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है, पर लाख टके की बात यह है जब तक हम अपने उद्योगपतियों को ताकत नहीं देते, विकसित देशों के उद्योगपतियों से मुकाबला कठिन है। हाल में रूसी प्रतिनिधिमंडल में तेल और ऊर्जा क्षेत्र के रोसनेफ्ट, स्बेयर बैंक, यूरिया उत्पादन से जुड़ी यूराल नेट, हथियार उत्पादन के लिए मशहूर रोजोबारोनेक्सपोर्ट जैसी कंपनियों के आला अधिकारी आए थे। वहीं भारत की ओर से टाटा, अंबानी, अदाणी किसी की भी रूसी प्रतिनिधिमंडल से सीधी बात नहीं हुई। ऐसा नहीं कि सीधी बात न होने से भविष्य में व्यापार की सारी संभावनाएं ही समाप्त हो गई हों, पर यह भी साफ है कि रूसी राष्ट्रपति की मौजूदगी में भारत की प्रमुख कंपनियों की उपस्थिति एक सकारात्मक असर डालती। यह अवसर हम चूक गए। शायद नीति निर्धारकों का सोच यह रहा हो कि कुछ अहम समूहों की उपस्थिति सियासी विवाद को जन्म देती और संसद सत्र के दौरान सरकार कोई मुद्दा विपक्ष को देने को तैयार नहीं थी। जरा सोचिए कि अफगानिस्तान में आतंक के दौरान भारतीय कंपनियों ने किन परिस्थिति में कार्य किया होगा और भारत सरकार ने तब उन्हें संरक्षण देकर सही किया या गलत? और आज फार्मा से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में निजी कंपनियों को अफगानिस्तान में भेजा जाना क्या जरूरी नहीं है? अफगानिस्तान ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, अफ्रीका आदि देशों में अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों से सहयोग लिया और आवश्यक संरक्षण प्रदान किया। घरेलू मोर्चे पर भी संकट के समय वैक्सीन का अतिरिक्त उत्पादन हो या ऊर्जा संकट के दौर में वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर, सभी कुछ निजी कंपनियों के जरिए हासिल किया गया, पर कभी तीन सौ तो कभी तीन व्यावसायिक समूहों के नाम पर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। भले स्वशासित राज्यों में उद्योगपतियों को महत्व देने के लिए खुलेआम भ्रष्टाचार तक का सहारा लिया गया हो। विपक्ष के नेता को वैचारिक खाद–पानी दे रहे एक वामपंथी नेता के पुत्र रियल स्टेट और बिस्किट फैक्ट्री के क्षेत्र में बंगाल के बड़े उद्योगपति बने। उनके उत्थान का काल सबसे लंबे दौर तक बंगाल में चला पिता जी का कार्यकाल ही रहा। उनकी ईस्टर्न बिस्किट कंपनी पर भी 37.68 लाख रुपये बकाये का केस बना। अदालत ने अन्य अपेक्षाओं के साथ पंद्रह लाख रुपये की बैंक गारंटी का आदेश दिया, जो नहीं भरी गई। बाद में अंतरिम आदेश रद हो गया। फाइल वर्षों बाद 2005 में मिली। आज वामपंथ के असर से मुक्ति पाकर बड़ी मुश्किल से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत ने तमाम कामयाबी हासिल की है। जापान पिछड़ चुका है और अब जर्मनी की बारी है, लेकिन सच यह भी है भारत की अर्थव्यवस्था जहां अब तक पांच ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर का आंकड़ा नहीं छू पाई है वहीं अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्थाएं तीस और बीस ट्रिलियन डालर से ऊपर की हो चुकी हैं। यानी अभी काफी कुछ किया जाना है, क्योंकि दुनिया आकाश से आई आवाज ही सुनती है। ताकतवर प्रतिद्वंद्वियों के साथ क्या करते हैं यह पहले चीन और फिर ट्रंप के बर्ताव से साफ है। दुनिया में आवाज शिखर की सुनी जाती है। बाकी आवाज या तो दब जाती है या उन आवाजों का दम घोंटने की कोशिश की जाती है। ट्रंप का मौजूदा रूप आपको यकीनन अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यह भी है कि ट्रंप से पहले भी समय–समय पर अमेरिका ने इसी तरह से भारतीय हितों में बाधा डालने का प्रयास किया था। यह बात अलग है कि डरावने नाखूनों वाले शरीर पर तब नफासत की नकाब लगी थी। याद कीजिए वह दौर जब भारतीय कपड़ों की खेप को यह कह कर लौटाया गया था कि इसमें आग लग जाती है। फलों की खेप कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग कह कर लौटा दी जाती थी, पर जब अमेरिकी पेय पदार्थों में कीटनाशकों का मामला आया तो पूरा अमेरिका प्रशासन मोर्चा संभालने लगा। जिस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी मोटर साइकिल कंपनी के हित को अपने देश का हित बता रहे हों, उस दौर में भारत के व्यवसायियों के वाजिब हितों के लिए कौन लड़ेगा? समाज और राजनीति, दोनों को व्यापार जगत के अपने योद्धाओं यानी उद्योगपतियों के प्रति रवैया बदलना होगा। ध्यान यह भी रहे व्यवसायियों को भी समाज के प्रति अपने दायित्व का पालन करना होगा।

सर्वाधिक असमानता वाले देशों की श्रेणी में बना हुआ है भारत

डॉ. ज्ञान

वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब ने असमानता को मापने का आधार आय को बनाया, न कि खपत को। ऐसा करने में वे ही सही हैं। मुफ्त अनाज, दवाएं, शिक्षा, या सब्सिडी वाली चीजें किसी गरीब को अमीर नहीं बनातीं, बल्कि सिर्फ उनकी जिंदगी के दुख को थोड़ा और सहने लायक बनाती हैं। इससे गरीब और अमीर के बीच असमानता खत्म नहीं होती। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि भारत दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा समान देशों में से एक है, लेकिन इसके सिर्फ पांच महीने बाद ही वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2026 में पाया गया है कि असमानता में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा असमानता वाले देशों की श्रेणी में बना हुआ है। इतना ही नहीं, हाल के सालों में इस मामले में बहुत कम सुधार देखा गया है। वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब द्वारा जारी वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2026 में कहा गया है, श्सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10प्रतिशत लोग राष्ट्रीय आय का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा लेते हैं, जबकि नीचे

के 50प्रतिशत लोगों को सिर्फ 15प्रतिशत मिलता है। धन की असमानता और भी ज्यादा है, जिसमें सबसे अमीर 10प्रतिशत लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 65प्रतिशत और शीर्ष 1प्रतिशत लोगों के पास लगभग 40प्रतिशत है। 2014 और 2024 के बीच शीर्ष 10प्रतिशत और नीचे के 50प्रतिशत के बीच आय का अंतर स्थिर रहा। प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय परचेजिंग पावरपैरिटी (पीपीपी) के आधार पर लगभग 6,200 यूरो है, और औसत संपत्ति लगभग 28,000 यूरो। महिला श्रम भागीदारी 15.7प्रतिशत पर बहुत नीचे के स्तर पर बनी हुई है, जो पिछले एक दशक में कोई सुधार नहीं दिखाती है। कुल मिलाकर, भारत में असमानता आय, धन और लिंग के आयामों में गहराई से जमी हुई है, जो अर्थव्यवस्था के भीतर लगातार संरचनात्मक विभाजन को उजागर करती है। जुलाई में भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की विज्ञप्ति में कहा गया था कि भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा समान देश है। यह दावा भारत सरकार के कई मंत्रियों और सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर साझा किया था। आधिकारिक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 (2022 के आंकड़ों के अनुसार) है, जो इसे श्मध्यम रूप से कम असमानताश श्रेणी में रखता है और इसे अमेरिका (41.8) और चीन (35.7) जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बाद, विश्व स्तर पर चौथा सबसे समान देश बनाता है। सरकार का दावा वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग 2025पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ पर आधारित था, जिसने गिनी गुणांक की गणना के लिए आय के आंकड़ों के बजाय उपभोग के आंकड़ों का इस्तेमाल किया था। खपत पर आधारित गिनी इंडेक्स आमतौर पर आय पर आधारित इंडेक्स की तुलना में असमानता की बेहतर तस्वीर दिखाता है। संक्षेप में, यह आंकड़ों की हेराफेरी थी। यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देकर खाना खिलाता है, और कई अन्य सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे मुफ्त चिकित्सा, शिक्षा, और सब्सिडी वाले उत्पाद और सेवाएं। इस सबको जोड़कर यह दिखाया गया कि खपत में कैसे सुधार हुआ है। यह आंकड़ों की कलाबाजी है जिसके आधार पर दवा किया गया कि उपभोग या खपत के मामले में धनियों और गरीबों के बीच असमानता कम हो गयी है। यही आंकड़ों की हेराफेरी है जो गरीबों की आय को नहीं बल्कि उसकी खपत, जिसका अधिकांश हिस्सा उसे दी गयी राहतें थीं, को आधार बना रही थी। फिर सरकार ने आईएलओ और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर दबाव डाला कि वे असमानता को मापने के लिए अपनी रिपोर्ट का आधार खपत को ही बनाएं, वास्तविक आय को नहीं। इसी खपत के आधार पर, वर्ल्ड बैंक ने भारत को दुनिया का चौथा सबसे समान देश बताया।

हालांकि, वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब ने असमानता को मापने का आधार आय को बनाया, न कि खपत को। ऐसा करने में वे ही सही हैं। मुफ्त अनाज, दवाएं, शिक्षा, या सब्सिडी वाली चीजें किसी गरीब को अमीर नहीं बनातीं, बल्कि सिर्फ उनकी जिंदगी के दुख को थोड़ा और सहने लायक बनाती हैं। इससे गरीब और अमीर के बीच असमानता खत्म नहीं होती। गरीब गरीब ही रहे, और अमीर और अमीर होते गए, जैसा कि आंकड़े दिखाते हैं। इसलिए, लोगों के बीच असमानता को मापने का आधार आय ही होनी चाहिए। जुलाई में मोदी सरकार के दावे को विपक्षी पार्टियों और अर्थशास्त्रियों से श्बौद्धिक रूप से बेईमानश और श्धोखाधड़ीश बताते हुए उसकी काफी आलोचना की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि खपत के आंकड़े का इस्तेमाल गुमराह करने वाला हो सकता है, क्योंकि आय का आधार आमतौर पर खपत की तुलना में असमानता की तस्वीर को बहुत ही व्यापक रूप से बदलती है। बहुत अमीर लोगों के बीच के आंकड़े ऐसे सर्वे में पूरी तरह से शामिल नहीं किया जा सकता। उस समय भी यह बताया गया था कि अगर आय के आधार पर मापा जाए तो भारत दुनिया में असमानता के मामले में 216 देशों में से लगभग 176वें स्थान पर होता। वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2026 कहती है कि 1980 में, वैश्विक अभिजात वर्ग मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया और यूरोप में केंद्रित था, जो मिलकर दुनिया के शीर्ष आय समूहों का अधिकांश हिस्सा थे। लैटिन अमेरिका की भी शीर्ष के पास कुछ उपस्थिति थी, लेकिन चीन और भारत लगभग पूरी तरह से वितरण के निचले आधे हिस्से तक ही सीमित थे। उस समय, वैश्विक अभिजात वर्ग में चीन की वस्तुतरू कोई उपस्थिति नहीं थी, जबकि भारत, सामान्य रूप से एशिया, और उप–सहारा अफ्रीका आदि के साथ बहुत नीचे था। 2025 तक, तस्वीर काफी अलग दिखती है। चीन की स्थिति ऊपर उठी हैरू उसकी ज्यादातर आबादी बीच के 40प्रतिशत में आ गई है, और एक बढ़ता हुआ हिस्सा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपरी–मध्य सेगमेंट में शामिल हो गया है। यह बात दूसरे एशियाई देशों पर भी लागू होती है। इसके उलट, भारत की स्थिति खराब हुई हैरू 1980 में, उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बीच के 40प्रतिशत में था, लेकिन आज यह नीचे के 50प्रतिशत में है। भारत का मध्यम वर्ग निचले स्तर पर ही बना हुआ है, जबकि चीन का हिस्सा बड़ा हो गया है। डब्ल्यूआईआर 2026 आंकड़ों को ऐतिहासिक नजरिए से देखता है जो दिखाता है कि 100,000 से कम आबादी वाले बहुत छोटे देशों ने 1970 से लगातार दुनिया के औसत से काफी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय दर्ज की है, और उनका सापेक्ष फायदा बढ़ा है। समय के साथ यह अंतर बढ़ता गया है। 2024 तक, उनकी आय वैश्विक औसत से लगभग चार गुना हो गई है। इसके उलट, दुनिया के औसत से लगातार कम आय वाले देशों की श्रेणी में सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन और भारत हैं। नतीजों में यह विविधता दिखाती है कि असमानता राष्ट्रीय संदर्भों के साथ कैसे जुड़ी रहती है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में जाति और धार्मिक पहचान आय और शिक्षा के बंटवारे के साथ काफी हद तक मेल खाती है। भारत में सबसे ऊपर के 1 प्रतिशत लोगों की औसत आय 140,649 यूरो है, जबकि उनकी औसत संपत्ति 1,128,435 यूरो, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत लोगों की आय और सम्पत्ति क्रमशरू सिर्फ 940 यूरो और 1801 यूरो।

जवाबदेही तय करने की जरूरत

विवेक

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस का परिचालन इस महीने की शुरुआत में ऐसा लड़खड़ाया कि अभी तक कुछ समस्याएं कायम हैं। विमानन बाजार में करीब 65 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली कंपनी की उड़ानों में देरी और उनके रद होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ना स्वाभाविक था। हालांकि अब कुछ स्थिति सुधरी है, लेकिन पूर्ण राहत अभी दूर है। सेवाओं में इस गतिरोध से न केवल लाखों हवाई यात्रियों को पीड़ा पहुंची, बल्कि इससे भारत की छवि पर भी आघात हुआ।

सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए इंडिगो पर कार्रवाई भी की है। यह तो जांच में ही सामने आएगा कि इस अराजकता के क्या कारण रहे, किंतु प्रथमदृष्ट्या पायलटों के लिए अधिक विश्राम संबंधी नियमों की पूर्ति के लिए अपेक्षित प्रयास न करने को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। कंपनी के पास पायलटों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय था, पर वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।

इंडिगो प्रकरण में एक प्रश्न यह भी उभरा है कि कंपनियों के मामले में सरकार को आखिर कब हस्तक्षेप करना चाहिए? समस्याओं के पहले या उनके उत्पन्न होने के बाद? विशेषकर तब जब उनकी लापरवाही से जनता और देश को नुकसान पहुंचने की आशंका हो। यह प्रश्न राजनीतिक जवाबदेही की ओर भी ले जाता है। यह मुद्दा किसी विशेष सरकार या पार्टी से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक वर्ग और भारत की राजनीतिक संस्कृति से संबंधित है। हमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी पीएसयू और निजी कंपनियों की प्रकृति एवं स्वरूप में अंतर को भी समझना होगा।

पीएसयू सरकारी स्वामित्व में होती है। उनकी जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों और विभागों की होती है। संबंधित मंत्री के माध्यम से सरकार इन सार्वजनिक कंपनियों को लेकर संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। निजीकरण से पहले विमानन में सरकारी कंपनी को ही अनुमति थी। तब एयरलाइंस ने अपने परिचालन को लेकर ऐसी लापरवाही दिखाई होती तधे नागरिक उड्डयन मंत्री को संसद में प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता।

यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का वास्तविक संचालन–प्रबंधन भी खांटी पेशेवरों द्वारा किया जाता है और संबंधित मंत्रियों से अपेक्षा नहीं की जाती कि वे रोजमर्रा के कामकाज में हस्तक्षेप करें। हालांकि, यह सुनिश्चित करना उनका राजनीतिक कर्तव्य है कि वे इसके लिए उचित व्यवस्था बनाएं। इस क्रम में वे वरिष्ठ लोकसेवकों को दायित्व सौंपते हैं। संबंधित लोक सेवकों को इन कंपनियों की स्थिति के बारे में सूचित रखना होता है। उनकी ओर से किसी भी उभरती समस्या के बारे में चेतावनी दी जाए। ऐसी संभावित समस्या जिससे लोगों के हित प्रभावित हो सकते हों। ऐसे में, मंत्री यह बहाना नहीं बना सकते कि लोक सेवक उन्हें अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि यह भी मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वे उचित लोक सेवकों का चयन करें जो अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाएं। कुल मिलाकर, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के मामले में सरकार और संबंधित मंत्रियों की संसद के प्रति और उनके माध्यम से जनता के प्रति राजनीतिक जवाबदेही सीधी होती है। यह एक अलग मामला है कि कई दशकों से राजनीतिक वर्ग ने हमेशा प्रशासनिक विफलताओं की जिम्मेदारी लोक सेवकों और प्रबंधकों पर डालने की कोशिश की है। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में मंत्रियों ने नैतिक जिम्मेदारी ली और यहां तक कि इस्तीफा भी दिया। वह दौर बहुत पहले ही बीत चुका है। मंत्रियों से जुड़ी कंपनियों में भ्रष्टाचार का मामला एक अलग श्रेणी में आता है।

उदारीकरण के साथ अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। इसका ही परिणाम है कि इंडिगो जैसी भीमकाय कंपनियां उभरीं, जो अपने बाजार के एक बड़े हिस्से पर काबिज होकर उसे नियंत्रित करती हैं। ऐसी स्थिति केवल कुछ कानूनों में परिभाषित आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों तक भी है जो ऐसे कानूनों के अंतर्गत नहीं आते। जैसे कि सीमेंट और बिजली उत्पादन क्षेत्र। इन क्षेत्रों में निजी कंपनियों की विफलता से अर्थव्यवस्था पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बड़ी निजी कंपनियां स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि कंपनियां कानूनों और नियमों के अनुसार संचालित हों। यह स्पष्ट है कि इंडिगो का बोर्ड अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा। चूंकि इन कंपनियों के संचालन में सार्वजनिक हित जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसे तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करें कि अधिकारियों को समय पर सूचित किया जाए कि कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होगा कि कंपनी के प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप होगा। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सरकार और कंपनियां दोनों संतुलन के साथ कार्य करें। यह अच्छी बात है कि राजनीतिक वर्ग और उद्योग जगत में इस मोर्चे पर परिपक्वता दिखती है। नियामकीय संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे इसकी निगरानी करें कि कोई कंपनी नियमों के पालन को लेकर सही दिशा में बढ़ रही है या नहीं। इंडिगो के मामले में नागरिक उड्डयन

महानिदेशालय यानी डीजीसीए की यही जिम्मेदारी थी। क्या डीजीसीए ने इस पर नजर रखी कि इंडिगो नए नियमों के अनुपालन को लेकर आवश्यक पायलटों की भर्ती के लिए प्रयास कर रही है? क्या उसने मंत्रालय के अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया, जिससे जानकारी और आगे बढ़ती। ये प्रश्न किसी को आलोचना के कठघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हैं ताकि इंडिगो प्रकरण से सबक सीखकर यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। जवाहदेही के राजनीतिक एवं प्रशासनिक मानदंड तो स्थापित करने ही होंगे। तेजी से वृद्धि कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में विमानन क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि इंडिगो की मौजूदा समस्याएं उन पहलुओं के समाधान तलाशने की दिशा में उन्मुख करें कि कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा जनता और अर्थव्यवस्था को न भुगतना पड़े। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र विशेष में किसी कंपनी का इतना वर्चस्व न हो जाए कि उसकी समस्याएं पूरे देश को नुकसान पहुंचाएं।

एक गड़बड़ी पर ध्यान

आदित्य

पराली जलाने संसद में दिए एक बयान में, पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि पंजाब और हरियाणा ने मिलकर 2022 के मुकाबले 2025 में "आग लगने की घटनाओं" में 90% की कमी की है। यह खेत की पराली जलाने के बारे में है, जो धान के बचे हुए खेतों को जल्दी से हटाने और उन्हें दूसरी फसल दृ इस मामले में, गेहूं दृ के लिए तैयार करने का एक पारंपरिक शॉर्टकट है, लेकिन पिछले डेढ़ दशक में इसे दिल्ली और आसपास के शहरों में अक्टूबर–नवंबर में एयर पॉल्यूशन में बढ़ोतरी से जोड़ा गया है। इससे निपटने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारें गाजर–और–डंडा वाला तरीका अपना रही हैं – किसानों पर जुर्माना लगा रही हैं, लेकिन साथ ही, उन्हें सब्सिडी वाले खेती के उपकरण, कंबाइंड हार्वेस्टर और ट्रैक्टर भी दे रही हैं, साथ ही उन्हें पराली इकट्ठा करने और उन्हें को–फायरिंग के लिए थर्मल प्लांट को बेचने के लिए बढ़ावा दे रही हैं। इस बात के बहुत कम सीधे सबूत हैं कि इन उपायों से दिल्ली की मॉनसून के बाद की हवा की क्वालिटी में पराली जलाने का हिस्सा कम हुआ है। इसके लिए समय के साथ पॉल्यूटेंट्स की केमिकल बनावट का एनालिसिस करने और पराली जलाने के वेटेज का पता लगाने के लिए मास–स्पेक्ट्रोग्राफ मेजर्स का इस्तेमाल करना होगा। वह एनालिसिस अवेलेबल नहीं है और इसलिए सरकार इस मेट्रिक को इवैल्यूएट करने के लिए सैटेलाइट्स से दिखने वाली एक्टिव आग की संख्या में कमी आई है या नहीं, जैसे प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रही है। 2020 से पंजाब और हरियाणा में आग लगने की घटनाओं में कमी आई है, जिससे सरकार को क्रेडिट लेना पड़ा। पता चला कि यह एक बेकार की जीत थी। जब एक अलग सैटेलाइट से इमेज का इस्तेमाल बर्न एरिया नाम के एक और पैरामीटर – असल में जला हुआ जमीन का एरिया – को कैलकुलेट करने के लिए किया गया, तो कमी धीरे–धीरे 30% हुई 2022 में लगभग 31,500 स्क्वायर किलोमीटर से 2025 में 19,700 स्क्वायर किलोमीटर (इस साल 25 नवंबर तक) तक, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गनाइजेशन ने पाया है।

केरल में कांग्रेस की जीत का मतलब

आदित्य

2025 में कांग्रेस ने महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार तीन महत्वपूर्ण राज्यों को गंवाया है, जबकि कांग्रेस ने इस बरस को संगठन की मजबूती का साल बनाया था। बार–बार उम्मीदों के विपरीत परिणाम आने से कार्यकर्ताओं

में थोड़ी निराशा आना स्वाभाविक है। लेकिन फिर साल के जाते–जाते कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है। केरल के नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेसनीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को बड़ी जीत मिली है। भले यह जीत दक्षिण के एक राज्य की है, लेकिन इसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। गौरतलब है कि केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसके साथ–साथ तमिलनाडु, प.बंगाल, पुडुचेरी और असम में भी चुनाव हैं। असम और पुडुचेरी में पहले से भाजपा की सरकारें हैं, शेष तीन पर भी वह स्वाभाविकतरू जीत हासिल करने की कोशिश में है। प.बंगाल में ममता बनर्जी के वोटबैंक में भाजपा सेंधमारी की तैयारी में है, यहां अब वाम मोर्चे और कांग्रेस के मुकाबले भाजपा मजबूत हो चुकी है। तमिलनाडु में भाजपा का खास जनाधार नहीं है, एआईएडीएमके के सहारे जो जमीन भाजपा तलाश रही थी, उसमें उसे सफलता नहीं मिली है। केरल में भी भाजपा कई बरसों से हाथ–पैर मार रही है। पिछले चुनावों में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई.श्रीधरन को भी भाजपा ने अपने खेमे में शामिल कर इस प्रगतिशील विचारधारा वाले राज्य को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। और अब नगरीय निकाय चुनावों में भी तिरुअनंतपुरम की नगर निगम जीतने के बावजूद भाजपा को केरल से झटका मिला है, क्योंकि यहां कांग्रेस लोगों की पहली पसंद के तौर पर उभरी है। कांग्रेसनीत यूडीएफ ने कोल्लम, कोच्चि, त्रिशूर और कन्नूर इन चार नगर निगमों के साथ 7 जिला पंचायतों, 54 नगर पालिकाओं, 79 ब्लॉक पंचायतों और 505 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की है। जबकि सत्तारुढ़ एलडीएफ को महज एक नगर निगम, सात जिला पंचायतों, 28 नगर पालिकाओं, 63 ब्लॉक पंचायतों और 340 ग्राम पंचायतों में जीत मिली है। एलडीएफ ने साल 2020 में हुए चुनाव में पांच नगर निगमों में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उसे सिर्फ कोझिकोड में ही जीत मिली है। इससे पता चलता है कि लोगों का भरोसा पिनराई विजयन के वाममोर्चे से ज्यादा कांग्रेस पर बढ़ा है। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने एक नगर निगम, दो नगर पालिकाओं और 26 ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र तिरुअनंतपुरम की नगरनिगम जीतने को भाजपा एक बड़ी जीत बता रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस जीत पर केरल की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि केरल की जनता यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुकी है। वहीं अमित शाह का कहना है कि केरल की जनता ने स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा और एनडीए को भारी जीत दिलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो तिरुवनंतपुरम में भाजपा की जीत को श्एक नए अध्याय की शुरुआत बताया है। अब जिस राज्य में एक अदद सीट के लिए भाजपा सालों साल तरसी है, वहां एक नगरनिगम में अपना महापौर बना लेना उसे बहुत बड़ी जीत लग सकती है। लेकिन अगर भाजपा अपनी मामूली जीत को बहुत बड़ी उपलब्धि बताएगी, तो क्या वह यह मानेगी कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में असली बाजी कांग्रेस के हाथ लगी है। क्योंकि उसने न केवल अपनी पिछली सीटें बरकरार रखी हैं, बल्कि सत्तारुढ़ मोर्चे से नयी सीटें भी हासिल की हैं। राहुल गांधी ने इस जीत के लिए केरल की जनता को सलाम भेजा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अब अगले साल के विधानसभा चुनावों में वह ऐसा ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि कांग्रेस को अपने पिछले अनुभव देखते हुए काफी फूंक–फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी बात रख रहे हैं। रुसी राष्ट्रपति पुतिन को दिए रात्रि भोज में राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को न बुलाकर भाजपा ने श्री थरूर को आमंत्रित किया। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के देशों में भारत का पक्ष रखने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शशि थरूर शामिल थे। अभी शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की लोकसभा में प्रदर्शन की समीक्षा के लिए जो बैठक बुलाई, उससे शशि थरूर नदारद थे। और अब अपनी संसदीय सीट के स्थानीय निकाय में भाजपा की जीत को वे लोकतंत्र की खूबसूरती बताते हुए न्यायसंगत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को इससे ज्यादा स्पष्ट संकेत नहीं मिल सकते कि अब उसे केरल की इस कमजोर कड़ी पर संभल कर एक्शन ले लेना चाहिए।

दुर्गाबाड़ी क्रासिंग पर महिला–बच्ची की मौत, एक घायल

गोरखपुर, संवाददाता। कोतवाली थाना क्षेत्र की दुर्गाबाड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास रविवार की शाम बाजार जा रहीं सविता यादव (32) और पड़ोस की दो बच्चियां सिया (8) और कनक उर्फ मिष्ठी (9) ट्रेन की चपेट में आ गईं। इस हादसे में सिया और सविता की मौत हो गई जबकि मिष्ठी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि क्रॉसिंग पार करते समय मालगाड़ी आती देख सविता बच्चियों के साथ दूसरे ट्रैक पर रुक गई थी, इसी बीच उस ट्रैक पर आई मोरध्वज एक्सप्रेस ने तीनों को चपेट में ले लिया। कोतवाली थाना प्रभारी छत्रपाल ने बताया कि हुमायूंपुर उत्तरी यादव टोला की रहने वाली सविता रविवार की शाम दुर्गाबाड़ी बाजार जाने के लिए घर से निकली थी। सामने के घर में रहने वाली सिया को उसने साथ चलने को कहा तो वहां खेल रही पड़ोस में रहने वाली मिष्ठी भी साथ चल पड़ी। घर से करीब 500 मीटर आगे गोरखनाथ के नए ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के कारण दुर्गाबाड़ी रेलवे क्रॉसिंग बंद मिली। सविता बच्चियों के साथ किनारे से ट्रैक पार करने के लिए बढ़ी तो मालगाड़ी आती देख दूसरे ट्रैक पर खड़ी हो गई। इसी बीच गोरखपुर जंक्शन से जम्मूतवी जा रही मोरध्वज एक्सप्रेस तेज रफ्तार में उसी ट्रैक पर आ गई, सविता और बच्चियां उसकी चपेट में आ गईं। इसके बाद गेटमैन ने जीआरपी और स्थानीय पुलिस को हादसे की जानकारी दी। पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सविता और सिया को मृत घोषित कर दिया। वहीं मिष्ठी को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्गाबाड़ी क्रॉसिंग पर हुए हादसे में सविता और मासूम सिया की मौत के बाद हुमायूंपुर उत्तरी यादव टोला में मातम है। अधिकतर घरों में चूल्हे नहीं जले और देर रात तक हादसे की चर्चा होती रही। आशंका जताई जा रही है कि बच्चियों के साथ दूसरे ट्रैक पर रुकी सविता मालगाड़ी के शोर में दूसरी ट्रेन के आने की आहट नहीं सुन पाई और मासूम सिया के साथ जान गंवा बैठी। हुमायूंपुर उत्तरी यादव टोला में रविवार की शाम रोज की तरह बच्चे धमा–चौकड़ी कर रहे थे। सिया (8) और कनक उर्फ मिष्ठी (9) भी गली में खेल रहीं थीं। सामने ही ऑटो चालक हेमंत यादव का मकान है। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक हेमंत की पत्नी सविता खरीदारी के लिए दुर्गाबाड़ी बाजार जाने के लिए निकली। उसने सिया से कहा कि बाजार चलो चॉकलेट दिलाऊंगी, यह सुनकर मिष्ठी भी साथ चल पड़ी। सिया ने सविता के मोबाइल से कॉल कर पिता अमित को बताया था कि कुछ देर में बाजार से लौट आएगी। घर से करीब 500 मीटर आगे दुर्गाबाड़ी क्रॉसिंग पर गोरखनाथ ओवरब्रिज निर्माण के कारण क्रॉसिंग बंद है। लोग अक्सर क्रॉसिंग के नीचे से दुर्गाबाड़ी की ओर जाते हैं। रविवार की शाम जब सविता बच्चियों के साथ क्रॉसिंग पर पहुंची तो एक मालगाड़ी वहां से गुजर रही थी। मालगाड़ी देख सविता, शिया और मिष्ठी दूसरे ट्रैक पर खड़ी हो गईं। तभी गोरखपुर स्टेशन से जम्मूतवी जा रही मोरध्वज एक्सप्रेस तेज रफ्तार में आ गई। दो ट्रेनों के शोर के बीच तीनों शायद खतरे को भांप नहीं सकीं और ट्रेन की चपेट में आ गईं। रविवार की शाम हुमायूंपुर उत्तरी यादव टोला के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। जिस गली में कुछ ही क्षण पहले तक बच्चों की हंसी की गूंज थी, अचानक चीख–चित्कार से पूरा मंजर बदल गया। हर दरवाजे पर शोक की चुप्पी थी। परिवार के लोग अस्पताल चले गए थे वहीं, सविता का छह साल का मासूम बेटा स्वास्तिक मां के लिए बिलख रहा था। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि 14 साल पहले सविता और हेमंत की शादी हुई थी।

डा. नरेंद्र देव अध्यक्ष, डा. भारतेंद्र जैन बने उपाध्यक्ष

गोरखपुर, संवाददाता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) का चुनाव रविवार को सीतापुर आई हॉस्पिटल स्थित आईएमए भवन में संपन्न हुआ। इसमें अगले साल के अध्यक्ष (प्रेसिडेंट इलेक्ट) पद के लिए डॉ. नरेंद्र देव ने जीत हासिल की है। डॉ. भारतेंद्र जैन उपाध्यक्ष बने। डॉ. आरपी शुक्ल ने वर्तमान सत्र के लिए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। चुनाव में 770 मतदाता थे। उनमें से 708 चिकित्सकों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. वीएन गुप्ता, डॉ. बीबी गुप्ता और डॉ. जेपी जायसवाल ने चुनाव संपन्न कराया। मतदान और मतगणना के बाद देर शाम सभी पदों पर विजेता प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। प्रेसीडेंट इलेक्ट पद पर डॉ. नरेंद्र देव और डॉ. नदीम अर्शद आमने–सामने थे। इसमें डॉ. नरेंद्र देव को 390 और डॉ. नदीम को 312 मत मिले थे। इस तरह डॉ. नरेंद्र ने 78 मतों से जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर मुकाबला तीन प्रत्याशियों के बीच था। इसमें डॉ .भारतेंद्र जैन 468 मत के साथ विजयी हुए। डॉ. महेंद्र गुप्ता दूसरे और डॉ. सीमा शाही तीसरे स्थान पर रहीं। कोषाध्यक्ष पद पर डॉ. देवेंद्र कुमार भगनानी ने 412 मत पाकर जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अमरेश कुमार सिंह को 139 मत से शिकस्त दी। डॉ. अमरेश को 273 मत मिले थे। डॉ. वाई सिंह पिछले वर्ष ही दो सत्र के लिए सचिव चुने गए थे। इसमें से उनका पहला सत्र समाप्त हो गया, जबकि इस नई कार्यकारिणी के साथ दूसरे सत्र की शुरुआत हो गई।

संक्षिप्त खबरें

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अंतर्गत हो रहे कार्यों का डीएम में किया औचक निरीक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारीधजिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र द्वारा तहसील मडियाहूं के सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अंतर्गत हो रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम

में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कार्यवाही गतिमान है जिसके अंतर्गत माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने कई प्रकार के डिफरेंसेज को सत्यापित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत जेंडर मिसमैच, आयु गैप, डुप्लीकेट, मृतक मतदाताओं की सूची सत्यापित की जानी है तथा रीवेरिफिकेशन किए जाने हैं। इस दौरान उन्होंने बीएलओ, सुपरवाइजर से संवाद भी किया उन्होंने निर्देशित किया कि जो भी विसंगतिया आई हैं उसको शीघ्र निस्तारित किया जाए, उन्होंने इस कार्य में लगे सभी कार्मिकों के कार्यों की सराहना करते हुए सभी का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर ईआरओ नवीन सिंह, सहित सुपरवाइजर बीएलओ आदि उपस्थित रहे।

माघ मेला पुलिस प्रशिक्षण शिविर से दी जा रही पुलिस कर्मियों को जानकारी

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स माघ मेला के त्रिवेणी सभागार में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित अधिकारियोंध्कर्मचारियों को साइबर निरीक्षक माघ मेला राजेश कुमार के द्वारा साइबर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराते हुए कैसे साइबर फ्रॉड से बचा जाए के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।क्षेत्राधिकारी जल पुलिस दिनेश कुमार यादव के द्वारा जल में यातायात, सुरक्षा और बचाव एवं स्नान घाटों पर सतर्कता पर विशेष वार्ता की गई तथा तृतीय कालांश मे अग्निशमन अधिकारी चंद्रशेखर यादव के द्वारा माघ मेला क्षेत्र में अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव व समय पर फायर अलार्म का प्रयोग,आग लगने पर बालू और पानी का उपयोग कैसे हो के सम्बन्ध में एक छोटा सा उदहारण प्रस्तुत किया गया।अंत में प्रशिक्षण के अंतिम कालांश में प्रभारी प्रशिक्षण धर्मेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा पाण्टून पुल, मुख्य मार्ग,भौगोलिक स्थिति एवं मेले का महत्व के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई।पुलिस अधीक्षक माघ मेला श्री नीरज कुमार पाण्डेय प्पै व अपर पुलिस अधीक्षकध्सहायक नोडल अधिकारी विजय आनंद के द्वारा सभी प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया गया।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सर्जन से 71.22 लाख की ठगी– रुपये मांगने पर दी जान से मारने की धमकी

गोरखपुर, संवाददाता। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जनरल सर्जन डॉ. दुर्गेश से जमीन के नाम पर 71.22 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि खुद को हॉस्पिटल संचालक बताने वाले व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों की मदद से जमीन बेचने का झांसा देकर रकम हड़प ली। बैनामा न होने पर रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित चिकित्सक की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों मनोज यादव, नेहा यादव, लालसा यादव, शिरीष मिश्रा, कमलेश यादव के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन के नाम पर रुपये हड़पने और धमकी देने का प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जनरल सर्जन डॉ. दुर्गेश त्रिपाठी जेमिनी पैराडाइज, मोगलहा में रहते हैं। उनका आरोप है कि कुशीनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के सुक्खड़ निवासी मनोज यादव से संपर्क हुआ, जिसने खुद को करीमनगर स्थित आर्शिया हॉस्पिटल का संचालक बताया। मनोज ने पिपराइच क्षेत्र के गढ़वा में 27 डिसमिल जमीन अपनी बताते हुए 60 लाख रुपये में सौदा तय कराया। वर्ष 2024 में 30 लाख रुपये एडवांस लेने के बाद उसने दूसरे की जमीन का एग्रीमेंट करा दिया। इसके बाद मनोज यादव ने चिलुआताल क्षेत्र के फत्तेपुर स्थित सात डिसमिल जमीन को अपनी दादी के ससुराल की नेहा यादव और लालसा यादव की बताते हुए 1.80 करोड़ रुपये में तय कराया। इसके लिए मनोज को 24 लाख रुपये नकद, नेहा यादव, लालसा यादव, शिरीष मिश्रा के खातों और वेंडर कमलेश यादव को कुल 41 लाख 22 हजार रुपये दिए गए।

प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला ने दिया बेटी को जन्म

गोरखपुर, संवाददाता। लखनऊ से आई सरयू–यमुना एक्सप्रेस ट्रेन में रविवार दोपहर बलिया की एक महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। महिला के पति की सूचना पर टीटीई ने गोरखपुर कंट्रोल रूम को सूचना दी। ट्रेन के गोरखपुर पहुंचने पर कोच से यात्रियों को नीचे उतारकर डॉक्टर ने प्रसव कराया। महिला ने बेटी को जन्म दिया, दोनों स्वस्थ थे। करीब आधे घंटे तक ट्रेन खड़ा रही, डॉक्टर से सलाह लेकर महिला और उसका पति बेटी के साथ ट्रेन से रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक, सरयू–यमुना एक्सप्रेस को रविवार को डायवर्ट कर अयोध्या की जगह गोरखपुर के रास्ते से चलाया गया। यह ट्रेन अमृतसर से आजमगढ़ के रास्ते जयनगर को जाती है। करीब दो बजे ट्रेन जब बस्ती से आगे बढ़ी तो ट्रेन एस–1 कोच में 43 नंबर बर्थ पर सवार बलिया के जगदेवा निवासी ममता देवी को प्रसव पीड़ा होने लगी। इसकी सूचना उनके पति अजय ने ट्रेन में मौजूद टीटीई को दी। टीटीई की सूचना पर लखनऊ कंट्रोल ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के यात्री मित्र कार्यालय पर जानकारी देकर डॉक्टर बुलाने को कहा। गोरखपुर यात्री मित्र कार्यालय पर मौजूद यात्री मित्र जयश्याम यादव ने रेल डॉ. सत्य प्रकाश और उनकी टीम को बुला लिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर पहुंची तो कोच में जाकर आरपीएफ की महिला जवानों ने यात्रियों को नीचे उतरवाया। इसके बाद डॉक्टर ने चेकअप किया और कोच में ही प्रसव कराया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक ट्रेन खड़ी रही। प्रसव के बाद ममता उनके पति अजय और नवजात बेटी के साथ उसी ट्रेन से अपने घर रवाना हो गए। ममता के पति अजय ने कहा कि यात्रा के दौरान उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से वे घबरा गए थे लेकिन अन्य यात्रियों ने हिम्मत दी और इसकी सूचना टीटीई को देने को कहा। टीटीई ने डॉक्टर को बुला कर उनकी पत्नी और बेटी की जान बचाई। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि जैसे गर्भवती महिला के हालत खराब होने की जानकारी मिली, महिला जवानों को डॉक्टर के साथ भेज दिया गया। सफलता पूर्वक प्रसव कराया गया, महिला ने बेटी को जन्म दिया। उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया लेकिन डॉक्टर से जरूरी दवाएं लेकर वे ट्रेन से ही चले गए।

संक्षिप्त खबरें

कागजों पर ही छात्रों को मिल गया पूरक पोषाहार

उन्नाव, संवाददाता। परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को एमडीएम के साथ पूरक पोषाहार के नाम पर सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को चिक्की बंटवाने का आदेश हुआ है। पिछले सप्ताह बुधवार को बीएसए स्तर से आदेश न होने से छात्रों को यह पोषाहार नहीं मिल पाया। जिले में संचालित परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई कर रहे 2.15 लाख छात्र–छात्राओं के लिए सरकार ने प्रत्येक सप्ताह दिनवार एमडीएम की व्यवस्था की है। मौजूदा समय में ठंड अधिक बढ़ गई है इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने दिसंबर से मार्च महीने तक छात्रों को पूरक पोषाहार के तहत सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को गुड़ की चिक्की बंटवाने का आदेश दिया था। इसके लिए कुल बजट के पांच प्रतिशत फंड का उपयोग फ्लैक्सी फंड से करने की व्यवस्था की थी। नियमानुसार 10 दिसंबर को इसका वितरण होना था लेकिन किसी भी स्कूल में चिक्की वितरित नहीं की गई। अधिकांश शिक्षकों का कहना है कि उनके पास इस संबंध में कोई आदेश नहीं पहुंचा। ऐसे में निदेशक का आदेश कागजों पर ही प्रभावी रहा। बीएसए शैलेष कुमार पांडेय ने बताया कि सभी खंड शिक्षाधिकारियों को स्कूलों में चिक्की वितरित कराने का आदेश दिया गया था। अगर नहीं बंटा है तो इसकी जानकारी ली जाएगी।

बजरंग इलेवन टीम बनी क्रिकेट चौंपियन

उन्नाव, संवाददाता। क्षेत्र के अहिरैरा में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को बजरंग इलवेन टीम ने जीत लिया। मुकाबले में सवाइन टीम को 68 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। रविवार को बजरंग इलेवन और सवाइन टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। सवाइन टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बजरंग इलेवन भगवंतखेड़ा की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में तीन विकेट खोकर 198 रन बनाए। टीम की ओर से मनीष ने शानदार 78 रन और दक्ष प्रताप सिंह ने 48 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सवाइन टीम 12 ओवर में 130 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। टीम के अनवर ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। बजरंग इलेवन के खिलाड़ी मनीष को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। यहां पर रिंकू सिंह, धर्मेंद्र सोनी, अमर यादव, विकास सिंह, आदी सिंह, उत्तम सिंह, हिमांशु सिंह आदि मौजूद रहे।

1619 बूथों पर 1.82 लाख बच्चों ने दी गई पोलियो की खुराक

उन्नाव, संवाददाता। जिले में रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। जिला महिला अस्पताल में बच्चे को पोलियो की खुराक देकर एसीएमओ डॉ. नरेंद्र सिंह ने अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं जिले में स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य जगहों पर बूथ लगाकर 1.82 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। जिला महिला अस्पताल में एसीएमओ डॉ. एचएन प्रसाद, एसीएमओ व जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. नरेंद्र सिंह और सीएमएस डॉ. राजीव गुप्ता ने बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाकर अभियान की शुरूआत की।

शॉर्ट सर्किट से रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, जान बचाकर बाहर भागे ग्राहक और कर्मचारी

पीलीभीत, संवाददाता। पीलीभीत के माधोटांडा कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित एक रेस्टोरेंट में सोमवार को शॉर्ट–सर्किट से आग लगने से अफरा–तफरी मच गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और फर्नीचर, काउंटर समेत अन्य सामान जल गया। आसपास के लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। रेस्टोरेंट स्वामी के अनुसार हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। माधोटांडा कस्बे में मुख्य मार्ग पर स्थित फार्म फूड नाम से एक रेस्टोरेंट है। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे रेस्टोरेंट में मौजूद ग्राहक और कर्मियों में हड़कंप मच गया। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शोर–शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हुए। इसके बाद आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। तब तक काउंटर, फर्नीचर समेत अन्य सामान जल गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जानकारी की। रेस्टोरेंट स्वामी का कहना है कि घटना से हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। थाना प्रभारी अशोक पाल ने बताया कि शार्ट सर्किट से आग लगने की वजह सामने आई है।

अंतर-महाविद्यालयी एथलेटिक्स मीट 19 दिसंबर से, पदकवीरों का होगा सम्मान

पीलीभीत, संवाददाता। बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय अपनी 50वीं स्वर्णिम अंतर– महाविद्यालयीय पुरुष व महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 19 से 21 दिसंबर तक विश्वविद्यालय परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों की सहभागिता अनिवार्य की गई है। प्रतियोगिता को लेकर विश्व विद्यालय प्रशासन ने सभी संबंधित महाविद्यालयों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय के क्रीड़ा सचिव प्रो. एसएस बेदी ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक महाविद्यालयों को पात्रता प्रपत्र सोमवार (15 दिसंबर) तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने होंगे। क्रीड़ा सचिव ने बताया कि पुरुष और महिला टीमों के लिए अलग–अलग दो–दो हजार रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक महाविद्यालय को दो हजार रुपये सुरक्षा निधि (धरोहर राशि) के रूप में जमा करनी होगी, जो प्रतियोगिता के सफल समापन के बाद वापस की जाएगी। प्रतियोगिता में उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी अपने–अपने महाविद्यालय के ध्वज के साथ मार्च पास्ट में शामिल होंगे। इसमें शामिल सभी खिलाड़ियों के लिए पंजीकरण के उपरांत चेस्ट नंबर लेना अनिवार्य होगा। बिना चेस्ट नंबर के किसी भी खिलाड़ी को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रो. बेदी ने बताया कि सत्र 2024–25 के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदकवीर खिलाड़ियों को इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न स्तरों पर पदक जीतकर संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ा चुके हैं।

1.10 लाख विद्यार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य

ज्ञानपुर, संवाददाता। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए जिले को एक लाख 10 हजार विद्यार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य मिला है। निदेशालय से पत्र आने पर शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को पत्र जारी कर छात्र–छात्राओं के पंजीकरण का निर्देश दिया है। सभी छह ब्लॉकों में पंजीकरण पर निगरानी रखने के लिए छह नोडल शिक्षकों की तैनाती की गई है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। आगामी दिनों में यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएससीई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इन दिनों हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में पंजीकृत विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा तैयारी करने में जुटे हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के मन में भय होता है। परीक्षार्थियों के मन से भय दूर करने के साथ तैयारी का मंत्र देने के लिए हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं।

प्रेम प्रसंग में झोलाछाप ने दोस्त संग मिलकर मजदूर का गला घोंटा

उन्नाव, संवाददाता। प्रेम प्रसंग में झोलाछाप ने दोस्त के साथ मिलकर बलियाखेड़ा गांव निवासी टेनरी मजदूर की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव दूसरे गांव में खाली खेत में फेंक दिया और ऊपर से घास डाल दी। तीसरे दिन किसानों ने शव देखा तो सूचना पुलिस को दी। परिजनों से जानकारी लेकर गांव के एक युवक को पुलिस ने उठाया तो मामले का खुलासा हुआ। मामले में पुलिस ने कानपुर निवासी झोलाछाप को गिरफ्तार कर लिया है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों पर प्राथमिकी दर्ज ली है। अचलगंज थानाक्षेत्र के बलियाखेड़ा गांव निवासी रामसजीवन का बेटा सुधीर पाल (25) टेनरी में मजदूर था। 12 दिसंबर की शाम गांव का ही रंजीत पाल उसे साथ लेकर गया था। रंजीत वापस आ गया था लेकिन सुधीर नहीं लौटा था। उसने परिजनों को अचलगंज तक साथ जाने और फिर सुधीर के बदरका गांव में छोड़कर कहीं अन्य जगह चले जाने की बात कही। बाद में घर वालों ने सुधीर की तलाश शुरू कर दी थी। रंजीत भी साथ में खोज करा रहा था। 13 दिसंबर को बदरका–छेरिहा गांव के बीच कच्चे रास्ते में एक होमगार्ड को बाइक पड़ी मिली थी जिसे बदरका चौकी में खड़ी कराया गया। पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर परिजन को सूचना दी थी। पुलिस के साथ रंजीत भी उस स्थान पर गया था लेकिन घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर मंगू के खेत में पड़ा शव नहीं नजर आया। रंजीत ने वहां पर गुमराह किया जिससे परिजन और पुलिस भी वहां से चली आई। रविवार सुबह खेत जा रहे किसानों ने झाड़ियों के बीच में शव पड़ा देखा। गले से रस्सी लिपटी थी। मुंह से खून निकल रहा था। ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि रोहित राजपूत को बताया तो उन्होंने बदरका चौकी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सीओ, एसओ बृजेश कुमार शुक्ला फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जांच में सुधीर की पैंट और अंडरवियर नीचे खिसकी हुई थी। पुलिस ने जब रंजीत को पूछताछ के लिए उठाया तो उसने कई बार बयान बदले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रंजीत ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है।

संकेतक न होने से निर्माणाधीन पुलिया में गिरी डीसीएम, सरियों में फंसा हेल्पर

पीलीभीत, संवाददाता। पीलीभीत–माधोटांडा मार्ग पर रविवार रात निर्माणाधीन सड़ा नाला पुलिया के पास हादसा हो गया। संकेतक और अन्य सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण डीसीएम पुल निर्माण में लगी सरियों में घुसकर अटक गई। हादसे में हेल्पर गंभीर घायल होकर डीसीएम में फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद वेल्डिंग मशीन से डीसीएम काटकर युवक को बाहर निकाला। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में माधोटांडा मार्ग पर निर्माणाधीन सड़ा पुलिया पर रविवार रात करीब 10:30 बजे हुआ। पीलीभीत से माधोटांडा की ओर जा रही डीसीएम अचानक निर्माणाधीन पुल के गहरे गड्ढे में जा गिरी और सरियों में फंसकर अटक गई। हादसे के बाद डीसीएम का चालक किसी तरह वाहन से निकलकर भाग गया, जबकि हेल्पर सरियों के बीच फंस गया। पैर का हिस्सा सरिया में फंसा होने से वह घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास गांव के लोग जमा हो गए।

सरियों के बीच फंस गया था युवक

हादसे की सूचना मिलने पर सुनगढ़ी पुलिस के साथ दमकल की टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सरिया के बीच फंसे हेल्पर को बमुश्किल बाहर निकाला गया। कुछ सरिया भी काटनी पड़ी। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल भिजवाया गया। जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार घायल युवक थाना न्यूरिया के ग्राम रतरनपुर निवासी ओमकार (40) है। पूछताछ में सामने आया कि वह चालक के साथ कलीनगर स्थित अपनी ससुराल जा रहा था। इंस्पेक्टर नरेश त्यागी ने बताया कि मामले में तहरीर नहीं मिली है। जांच के बाद संबंधित कार्यदायी संस्था के कर्मियों को निर्माण स्थल पर हादसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्रामीण बोले, संकेतक व बैरियर न होना रही हादसे की वजह

सड़ा गांव के लोगों का कहना है कि करीब आठ माह पूर्व पुलिया निर्माण शुरू कराया गया। बरसात के चलते कार्य बंद रहा। इसके बाद भी कार्य की गति धीमी रही। निर्माण क्षेत्र में एक ओर ठेकेदार की ओर से मार्ग पर ही कैंप लगाकर रास्ते का रोका गया है।

किसान पाठशाला अभियान आज से

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर 16 दिसम्बर – शासन किसानो की आय बढ़ाने के लिये कई महत्वपूर्ण योजनाये चला रही है। रबी अभियान के लिये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति के लिये 13 दिसम्बर 2025 से 29 दिसम्बर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तरीय रबी गोष्ठी ध किसान पाठशाला अभियान चलेगा। उप कृषि निदेशक हिमांशु पाण्डेय ने बताया कि अभियान का रोस्टर जिलाधिकारी डा० दिनेश चन्द्र द्वारा जारी कर सम्बन्धित अधिकारियो को प्रभावी तरीके से कार्यक्रम करने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 625 ग्राम पंचायतो में 02 दिवसीय किसान पाठशाला आयोजित होगी, जिनमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि एवं सम्बन्धित विभागो के अधिकारी ध कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, जो रोस्टर के अनुसार निर्धारित गाँवो में 02 दिनो तक कार्यक्रम करेंगी, जिसमें उन्नत तकनीकियो एवं विभागीय योजनाओ से कृषको को जागरूक किया जायेगा, ताकि किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर अपनी समृद्धि करते हुये कृषि का सतत् विकास कर सकते है।

माँ बाप ने गैर समुदाय की लड़की से शादी को नही कर रहे थे स्वीकार, हो सकता है हत्या का कारण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 16 दिसंबर। यूपी के जफराबाद थाना अंतर्गत एक दिल दहला देने वाली घटना सोमवार को रात सामने आई है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कलयुगी पुत्र का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है।कलयुगी पुत्र ने अपने बुजुर्ग मां बाप की पैसों और प्रापर्टी के लिय हत्या कर शव को बोरे में भरकर गोमती नदी में फेंक दिया और फरार हो गया। जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में इकलौते बेटे ने पैसे के विवाद में बुजुर्ग रिटायर्ड लोकोपायलट–पिता और मां की सिर पर सिलबट्टे से वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शवों को बोरे में भरकर गोमती नदी में फेंक दिया। गांव निवासी श्यामबहादुर के पास तीन पुत्रियां तथा एक पुत्र है।उसका पुत्र अम्बेश कुमार दूसरे नम्बर पर है। अम्बेश कुमार कोलकाता रहता था।वह वहां पर प्रेम विवाह करके परिवार व दो बच्चो के साथ रहने लगा।तीन माह से वह अकेला घर आ गया था।वह अपने पिता श्यामबहादुर से पैसे को लेकर आये दिन विवाद करने लगा। उसके द्वारा किये इस व्यवहार के बाद उसके पिता उससे काफी नाराज रहने लगे।इस दौरान अम्बेश को लगा कि उसके पिता उसकी बहनों को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहते है।वह पिता से पैसा लेना चाहता था।पिता ने पैसा देने से मना किया।इससे आक्रोशित पुत्र ने पिता श्यामबहादुर (65) तथा अपनी माँ बबिता देवी (63) को काटकर बोरे में भर कर गोमती नदी में ले जाकर फेक दिया। घटना बीते आठ दिसंबर को हुई। घटना के पांच दिन बाद वाराणसी में रहने वाली बेटी ने गुमशुदगी की

रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में शक होने पर पुलिस ने सोमवार की रात आरोपी कलयुगी पुत्र अम्बेश कुमार को पकड़ा तो उसने हत्या का खुलासा किया। एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि वंदना देवी ने 13 दिसंबर को अपनी माता बबिता देवी और पिता श्याम बहादुर की गुमशुदगी की सूचना जफराबाद थाने में दर्ज कराई थी। वंदना ने पुलिस को बताया था कि 8 दिसम्बर से उनके माता–पिता लापता हैं। उनका भाई अम्बेश भी लापता है, जो माता–पिता को ढूंढने निकला है।तीनों की बरामदगी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित कीं गयी।सोमवार की शाम अम्बेश कुमार को घर के पास से पकड़कर गहनता से पूछताछ शुरू की तो उसने माता–पिता के हत्या की हैरान कर देने वाली घटना बताई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि आठ दिसंबर की रात आठ बजे पारिवारिक विवाद और पैसों को लेकर माता–पिता से उसकी लड़ाई हो गई थी। उस दौरान उसने अपने माता–पिता के सिर पर सिलबट्टे से प्रहार कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। इसके बाद शवों को ठिकाने लगाने के लिए उसने बोरे में भरकर गोमती नदी में फेंक दिया। एसपी सिटी ने बताया कि मामले के खुलासे के बाद तत्काल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी पुत्र अम्बेश कुमार से गहनता से पूछताछ कर रही है। उसकी निशानदेही पर शवों की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। मंगलवार की इस मामले की पुलिस छानबीन करने में जुटी है।घर पर पहुंची फॉरेंसिक टीम अपर पुलिस अधीक्षक शहर आयुश श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी शहर गोल्डी गुप्ता के नेतृत्व में नमूना संग्रह किया है।घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए तीन टीम गठित कीं, जिसके बाद जांच शुरू हुई। इधर, घूमते–घूमते आरोपी अम्बेश कुमार वाराणसी चला गया। जहां उसने गंगा स्नान भी किया और घाट पर घूमते भी देखा गया। इसके बाद वह घर के नजदीक आने लगा तो खोजबीन में जुटी पुलिस ने उसे बरामद किया। पुलिस के सवालों में अम्बेश कुमार उलझ गया और माता–पिता की हत्या की पूरी कहानी बता दिया। मृतक श्यामबहादुर केराकत के खरगसेनपुर गांव के रहने वाले थे।उनको यहाँ पर उनके ससुर स्वर्गीय रामनारायण ने अपनी संपति दे दिया था।श्यामबहादुर टाटा जमशेदपुर में रहते थे।वे रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात थे।

बंगाली कायस्थों को साधने के लिए नितिन को बागडोर : जितेन्द्र बच्चन

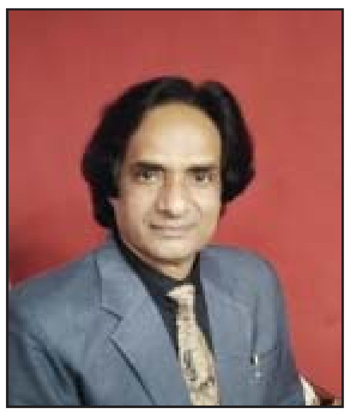

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

गाजियाबाद।पश्चिम बंगाल में खेला होगा, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन खेल का असली मदारी कौन है, यह नितिन नबीन की ताजपोशी से पता चलता है। नितिन को देश की सबसे बड़ी पार्टी का ताज उस दौर में मिला है जब बिहार से लेकर देशभर में जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति केंद्र में है। कायस्थ समाज के नितिन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पीएम मोदी ने सियासत की बाजी पलट दी है। बीजेपी के ऐलान ने जहां उन तमाम अटकलों को गलत साबित कर दिया जिनमें बड़े दिग्गजों को पार्टी की कमान सौंपने की चर्चा हो रही थी, वहीं 45 साल के नितिन नबीन पर दांव खेलकर मोदी ने श्मिशन बंगालश को लेकर अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं।

पश्चिम बंगाल में कायस्थों की अच्छी खासी आबादी है और उन्हें ब्राह्मणों व वैद्यों के साथ बंगाल की पारंपरिक उच्च जातियों (भद्रलोक) में गिना जाता है, जो शिक्षा, लेखन और प्रशासन से जुड़े हुए हैं। बंगाल में आजादी के बाद 37 साल तक कायस्थों के हाथ में सत्ता रही है और करीब 24 लाख मतदाता इस वर्ग के हैं। बंगाल में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले ज्योति बसु भी कायस्थ थे। यहां के कायस्थ सदियों से भूमिधर हैं। बंगाल के सामाजिक–आर्थिक ताने–बाने में उनका महत्वपूर्ण वर्चस्व है। ऐसे में मोदी का मानना है कि कायस्थ्य समाज के नितिन नबीन बीजेपी के लिए बंगाल विधानसभा चुनाव में ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं और उनके संकेत पर पार्टी ने 14 दिसंबर को नितिन नबीन को जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह यह नियुक्ति भाजपा के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय नेता रूप में दर्ज हो गई है।

दरसअल, बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में बीजेपी ने पारंपरिक रूप से कायस्थ बहुल सीटों, जैसे कुम्हरार में कायस्थ उम्मीदवारों के टिकट काट दिए या उनकी जगह दूसरी जातियों के उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। इससे कायस्थों में यह भावना पैदा हो गई कि पार्टी उन्हें कम महत्व दे रही है। इससे पहले केंद्र और राज्यों के मंत्रिमंडल में भी कायस्थ संगठनों की शिकायत रही है कि उनके समाज के विधायकों को मंत्रिमंडल में उचित स्थान नहीं दिया गया, जबकि पार्टी का कायस्थ समाज वफादार मतदाता रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय के नेताओं को समायोजित करने की बीजेपी की सामाजिक इंजीनियरिंग नीति में भी कायस्थों को हाशिए पर धकेल दिया गया। इससे कायस्थों में असंतोष पनपने लगा, जिसे दूर करने के प्रयास में बीजेपी ने बिहार के कायस्थ नेता नितिन नबीन को पार्टी की बागडोर सौंप दी। नरेंद्र मोदी के इस कदम को कायस्थ समाज के बीच डैमेज कंट्रोल (नुकसान की भरपाई) के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मोदी के इस फैसले से कायस्थ समाज की नाराजगी भी दूर हो गई और बंगाल के कायस्थों का वोट मिलना भी अब पक्का माना जा रहा है।

साकेत पुरी स्थित निर्मला हॉस्पिटल पर लापरवाही का मरीज के परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।साकेत पुरी स्थित निर्मला हॉस्पिटल पर एक मरीज की मौत के बाद गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है।सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है,जिसमें अस्पताल प्रशासन की कथित गलती को स्वीकार किए जाने की बात कही जा रही है।मृतका के परिजन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप–मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, और पुलिस प्रशासन से हॉस्पिटल को तत्काल सील करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। परिजनों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, एक मरीज जो पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थीं और सोमवार सुबह ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटने वाली थीं, उन्हें सुबह एक षलत इंजेक्शनष दिया गया। आरोप है कि इस इंजेक्शन के ओवरडोज के कारण अचानक उनकी पल्स (नाड़ी दर) गिरकर 30 से 40 तक आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनन–फानन में डॉक्टर द्वारा उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। हालांकि, लखनऊ पहुंचते–पहुंचते मरीज की हालत बेहद गंभीर हो गई और कथित दवा के

रिएक्शन तथा ओवरडोज के कारण शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। लखनऊ में डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद, अत्यधिक नुकसान हो जाने के कारण मरीज ने दम तोड़ दिया।परिजनों का दावा है कि डॉ. आर.के. बनोधा ने स्वयं लिखित रूप में अपनी श्गलती को माना है'।इसके अलावा अस्पताल के स्टाफ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित तौर पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि दवा के ओवरडोज के कारण ही मरीज की जान गई है।मृतक के मित्र ने सोशल मीडिया पर मार्मिक पोस्ट करते हुए लिखा है,ष्सरकार और पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे लापरवाह डॉक्टर और उनकी हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाय,जिससे आगे किसी मासूम को इनकी लापरवाही से जान न गवानी पड़े।क्या बोले सीएमओ इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में है।इस मामले में पीड़ित द्वारा शिकायती पत्र दिये जाने पर जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर अस्पताल प्रशासन पर कार्यवाही की जाएगी।

एआरएम, एआरटीओ प्रशासन व एसपी ग्रामीण ने वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सावधानी बरतने की अपील

(डॉक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।कोहरा व ठंड के समय बाइक, जीप, कार, रोडवेज बस, ट्रक व हल्के तथा भारी वाहनों को चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।सभी वाहन चालकों से एआरएम आदित्य प्रकाश,एआरटीओ प्रशासन डाक्टर आरपी सिंह,एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने संयुक्त रूप से सभी वाहन चालकों से अपील किया है की आने वाले दिनों में कोहरा और ठंड और भी बढ़ेगी इसके चलते हम सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है।आने वाले दिनों में हल्के व भारी वाहन चालक विशेष सावधानी बढ़ाते हुए वाहन चलाएं।इन अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील किया कि क्योंकि आने वाले दिनों में जहां एक ओर ठंड होने के चलते बाइक के साथ–साथ हल्के व भारी वाहनों को नियंत्रित कर पाना मुश्किल रहता है।वहीं कोहरे के दौरान कम दृष्टता के चलते भी वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों की संभावनाएं बनी रहती हैं जिसके चलते सभी वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। बताया कि ठंडी के समय में सड़क यात्रा करने में कोहरा एक बड़ी समस्या साबित होता है, और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। उन्होंने बताया कि को हरे को धरातल पर बादल के समतुल्य मान सकते है।इन वाहन चालकों से अपील किया है कि घना कोहरा होने के कारण आगे कम दिखता हैजिसके कारण दुर्घटनाएं बढती है। कहा कि चालक कुछ सावधानियों बरतें और दुर्घटनाओं से बचें।कोहरे में अपने वाहन को धीमी गति से चलायें।वाहन की हेडलाईट लो बीम पर रखें।हाई बीम पर रखने पर हेडलाईट का प्रकाश कोहरे से वापस लौट कर दृश्यता को और भी कम कर देता है, कोहरे में फाग लाइंट का प्रयोग करें।वही अपने वाहन के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर के अलावा इंडिकेटर जलते बुझते (ब्लिंक) रखें ताकि आपके पीछे से एवं सामने आने वाले वाहन आपको देख सके।वाहन चलाते समय धैर्य बनाये रखें और ओवरटेक कतई न करें।वाईपर और डिफ्रास्टर को चलाकर विंडस्क्रीन साफ रखें।इसके लिये हल्का हीटर चलायें तथा ब्लाृअर की हवा विंडस्क्रीन की ओर कर दे। वही अपनी खिडकी के शीशे पूरी तरह बन्द न रखें। उन्हें थोडा खुला रखें ताकि दिखायी न पडने वाले वाहनों की आवाज सुनकर उनकी उपस्थिति का ज्ञान हो सके। वाहन चलाते समय स्टीरियो या एफ एम को बन्द कर दें।इन अधिकारियों ने कहा कि कोहरे के कारण अक्सर दृष्टि भ्रम हो जाता है।दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन से आगे एवं पीछे चल रहे वाहन से एक निश्चित दूरी बनाये रखे, तथा ब्रेक धीर लगाये ताकि पीछे चल रहे वाहन को भी ब्रेक लगाने का पर्याप्त समय मिल सके।कभी कभी कोहरा थोडी–थोडी दूरी पर मिलता है।व्यवसायिक वाहनों में आगे की ओर सफेद व पीछे की ओर लाल रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगा होना अनिवार्य है।ओवरटेक करते समय सड़क के बीच में खराब खड़े व सड़क किनारे पार्क किये गये वाहनों से सावधान रहें।

संक्षिप्त खबरें

अमरेंद्र कुमार खरवार जिला महामंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चा गाजीपुर एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी जखनिया चतुर्थ ने दी बधाई

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ।छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य आदरणीय श्री रामकिशुन सिंह जी को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सरगुजा अंबिकापुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने पर बहुत–बहुत बधाई। अमरेंद्र कुमार खरवार जिला महामंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चा गाजीपुर, अनूप सिंह खरवार क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा काशी क्षेत्र, विनोद खरवार क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा काशी क्षेत्र।

जगमग जी गांव गिरांव के परिवेश के कुशल चितेरे – डॉ दिनेश चन्द्र

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जगमग जी की कहानी जौनपुर के ग्रामीण अंचल, संस्कृति, संस्कार, विचार, व्यवहार को देश के कोने–कोने में पहुंचाएगी। जगमग जी गांव गिरांव के परिवेश के कुशल चितेरे हैं। उक्त विचार जयन्त्री प्रसाद श्जगमगश द्वारा लिखित कहानी संग्रह श्इक्यावन जगमग कहानियाँश के लोकार्पण के शुभ अवसर पर बुधवार को अपने कार्यालय में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी जौनपुर डॉ दिनेश चन्द्र ने व्यक्त किया। जिलाधिकारी जौनपुर ने जयन्त्री प्रसाद श्जगमगश्के लेखन शैली की प्रशंसा करते हुए निरंतरता के साथ लिखने के लिए प्रेरित भी किया। बतौर विशिष्ट अतिथि प्रख्यात साहित्यकार डॉ ब्रजेश कुमार यदुवंशी ने कहा कि जगमग जी की ग्रामीण कहानियां क्लिष्ट भाषा शैली की अपेक्षा गांव गिरांव के जीवन, संस्कृति और भावनाओं को उभारने पर कुछ ज्यादा केंद्रित हैं। लेखक अक्सर गांव की सीधी–सादी बोली, किसानों की समस्याएं, स्थानीय रीति रिवाज और प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, न कि किसी परिष्कृत साहित्यिक शैली का। सीआरओ अजय कुमार अम्बष्ट ने कहा कि कहानी संग्रह इक्यावन जगमग कहानियां ग्रामीण चेतना का सशक्त दस्तावेज है। यह कहानी संग्रह केवल मनोरंजन का साधन नहीं अपितु आत्म चिंतन और संवेदनशीलता को जागृत करने का सशक्त माध्यम भी है। विदित हो कि कुछ महीने पहले जिलाधिकारी जौनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कवि, लेखक जयन्त्री प्रसाद जगमग के नाम से मुख्य मार्ग से पालपुर गांव तक जाने वाली सड़क का नाम जगमग मार्ग कर दिया है। इस महान कार्य के लिए क्षेत्रीय लोगों ने जिलाधिकारी जौनपुर का आभार भी प्रकट किया है। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों के साथ गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

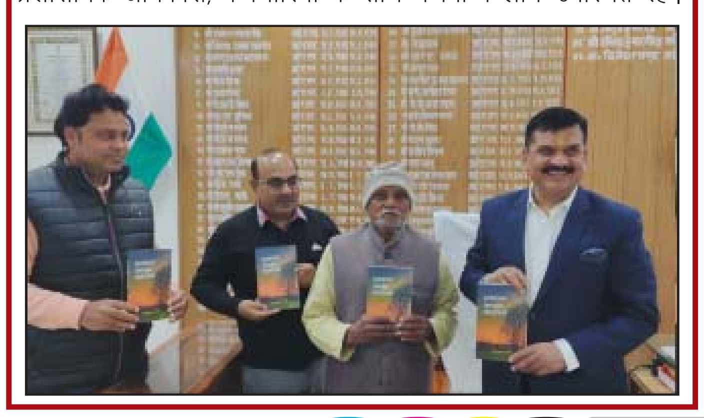

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने लॉन्च की ऑल न्यू हेक्टर

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने आज ऑल–न्यू एमजी हेक्टर के लॉन्च की घोषणा की। यह एसयूवी सेगमेंट में बोल्ड डिजाइन, बेजोड़ आराम, अग्रणी तकनीक और डायनामिक ड्राइविंग अनुभव के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। आज यहां चिनहट स्थित एमजी मोटर्स के शोरूम में ऑल–न्यू एमजी हेक्टर की लांचिंग के मौके पर मि. रवि मित्तल, डायरेक्टर स्ट्रैटजिक प्रोजेक्ट्स, जेएसडब्लू एमजीआई, रजनीश अग्रवाल, डायरेक्टर, बीआर एमजी,, आरिफ खान, सेल्स हेड, बीआर एमजी, मि. आलोक मिश्रा, सर्विस हेड बीआर एमजी मौजूद थे। पेश की गयी ऑल–न्यू हेक्टर में नया फ्रंट और रियर बंपर डिजाइन है। साथ ही बिल्कुल नया ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स और दो नए रंग सेलेडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइट शामिल हैं। इसके इंटीरियर्स में 5–सीटर वेरिएंट के लिए ड्यूल टोन आइस ग्रे थीम और 6 व 7–सीटर वेरिएंट्स के लिए ड्यूल टोन अर्बन टैन थीम दी गई है। यह केबिन को और अधिक प्रीमियम व आकर्षक बनाती है। ऑल–न्यू एमजी हेक्टर रेंज की शुरुआती कीमत 11.99

लाख रुपए (केवल सीमित इकाइयों के लिए) है। लॉन्च के अवसर पर अनुराग मेहरोत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने कहा, हेक्टर हमारा पहला नेमप्लेट था और जल्द ही यह एमजी ब्रांड का पर्याय बन गया। आज तक 1.5 लाख से अधिक ग्राहकों ने इसे पसंद किया है। ऑल–न्यू एमजी हेक्टर के साथ हम इसके डिजाइन, कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी को और ऊंचे स्तर पर ले जा रहे हैं। हमारा मानना है कि उन्नत मोबिलिटी कुछ लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ऑल–न्यू हेक्टर टेक्नोलॉजी को और अधिक लोकप्रिय बनाते हुए प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में नए मानक स्थापित करेगा।" ऑल–न्यू एमजी हेक्टर में नया औरा हेक्स ग्रिल दिया गया है, जो मजबूती और सटीकता का प्रतीक है। इसके साथ फ्रंट और रियर में नए औरा स्कल्प्ट बंपर्स हैं, जो हर एंगल से एक मस्क्युलर और आत्मविश्वासी स्टांस देते हैं। औरा बोल्ट अलॉय व्हील्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे खड़े–खड़े भी ताकत और स्टाइल का एहसास कराएं। नए एक्सटीरियर रंगकृसेलेडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइटकृइसके आधुनिक और प्रीमियम लुक को और निखारते हैं। ऑल–न्यू एमजी हेक्टर के शानदार इंटीरियर्स में अब दो नए कलर थीम्स मिलते हैंकृ ड्यूल टोन अर्बन टैन (6 और 7–सीटर वेरिएंट्स के लिए), जो आधुनिक शहरी सौंदर्य से प्रेरित है और गर्मजोशी भरा है। यह लग्जरी का अहसास देता है। ड्यूल टोन आइस ग्रे 5–सीटर वेरिएंट के लिए है। इसमें ब्लैक–ग्रे पैलेट के साथ एक रिफाइंड और टेक–फॉरवर्ड माहौल मिलता है। इंटीरियर्स को हाइड्रा ग्लोस फिनिश एक्सेंट्स के साथ और बेहतर बनाया गया है।

संक्षिप्त खबरें

नगर निगम में कई वर्षो से जमे कर्मियों की पटल में परिवर्तन होने से विभाग में मचा हड़कंप

राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या। नगर निगम में काफी साल से एक ही पटल पर कुंडली मारकर बैठे सहायक अभियंता से लेकर आउट सोर्सिंग लिपिक तथा कंप्यूटर ऑपरेटर के पटल पर फेरबदल हो गया है।जिसके चलते काफी वर्षों से एक ही पटल पर बैठे सहायक अभियंता अवर अभियंता लिपिक के साथ–साथ कंप्यूटर ऑपरेटरो मैं हर काम मच गया है। विभाग में तैनात कर्मियों ने बताया कि यह कार्यवाही बहुत दबाव के बाद की गई है क्योंकि यहां पर कई सालों से जेम सहायक अभियंता अवर अभियंता लिपिक वह कंप्यूटर ऑपरेटर की शिकायत शिकायतकर्ताओं ने ऊपर तक भी की थी जिसका नतीजा यह रहा की उनके कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया है फिर बादल की कड़ी में सबसे अधिक प्रभावित निर्माण कार्य विभाग आया है क्योंकि कई बार वहां पर तैनाद विभाग के कर्मचारियों की माने तो निर्माण कार्य के नाम पर टेंडर सहित अन्य कई मामलों में भी वहां पर तैनात सहायक अभियंता से लेकर अवर अभियंता लिपिक तथा कंप्यूटर ऑपरेटर पर उंगलियां भी उठती रही है। इसके अलावा नगर निगम के कर विभाग स्वास्थ्य विभाग जलकल विभाग अमानीगंज प्रकाश विभाग रिकॉर्ड विभाग कार्यशाला सहित अन्य प्रमुख विभागों में काफी दिनों से तैनात इन कर्मचारियों के पटल में परिवर्तन किया गया है। बताया जाता है की इन पटलों पर तैनात जिन कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है वे लोग काफी वर्षों से एक ही पटल पर जमे हुए थे। इन लोगों की शिकायत जब बार–बार उच्च अधिकारियों महापौर को मिली तो उनके पटल में फेर बदल करने की यह कार्यवाही की गई। वही इस कार्यवाही के चलते कई ऐसे लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ–साफ दिखाई दे रही थी जो लोग अपने–अपने कामों पर आवाज में उनसे संपर्क साधा था लेकिन एक दूसरे से कान्हा पूसी करते हुए नजर आ रहे थे कि अब दूसरे लिपिक के तैनात होने पर ही उनके काम में क्या होगा यह तो वहां पर तैनाश संबंधित लिपिक या अधिकारियों के आने पर ही होगा।

'जन सुनवाई मे जिलाधिकारी ने सुनी 44 शिकायतें'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' मंगलवार को कलेक्ट्रेट कक्ष में जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन की समस्याओं को सुना तथा जन सुनवाई में कुल 44 शिकायतेन प्राप्त हुई, जिसके त्वरित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित को दिए। आज जन सुनवाई में एक व्यक्ति का राशन कार्ड, एक महिला को निराश्रित महिला पेंशन, एक दिव्यांग पेंशन तथा एक आयुष्मान कार्ड बनाया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्व और गुणावत्तापूर्ण ढंग से हो। राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण लंबित न रखें तथा कृषक दुर्घटना बीमा योजना के किसी आवेदन को लंबित न रखा जाये। इस अवसर पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अरूणिमा श्रीवास्तव व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारीध्कर्मचारी उपस्थित रहे।

'नामावलियों का पुनरीक्षण कार्य आयोग द्वारा निर्धारित समय में पूर्ण कराया जायेगा–अनुनय झा'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' मंगलवार को स्वामी विवेकानन्द सभागार कलेक्ट्रेट में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के सम्बन्ध में आहूत बैठक की अध्यक्षता में जिलाधिकारीधजिला निर्वाचन अधिकारी अनुनय झा ने उपस्थित समस्त दलों के राजनैतिक प्रतिनिधियों से निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण पर चर्चा की तथा बताया कि निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत मतदाताओं को संबंधित क्षेत्र के बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र प्राप्त कराकर एवं वांछित सूचनाओं सहित भरवाकर प्राप्त किया जा रहा है और कार्य को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय में पूर्ण कराया जायेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एसडीटी की सूची समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गयी है। बैठक में प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहें।

लायन्स क्लब व शंकरा आई हास्पिटल के निशुल्क आंखों के मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में लाभान्वित हुए जरुरतमंद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर लायन्स क्लब जौनपुर मेन और आर जे शंकरा आई हास्पिटल वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र जांच मोतियाबिंद आपरेशन व लेन्स प्रत्यारोपण शिविर स्थान लक्ष्मी हेल्थ केयर सेंटर निकट कुत्तुपुर तिराहा पर आयोजित किया गया है। इस शिविर में 117 लोगों की आंखों की जांच की गई। जांच में 24 रोगी मोतियाबिंद से ग्रसित पाए गए, जिन्हें निशुल्क ऑपरेशन के लिए वाराणसी रवाना किया गया।शिविर में आर जे शंकरा आई हॉस्पिटल वाराणसी की नेत्र चिकित्सक डॉ. अल्का यादव और उनकी चिकित्सकीय टीम (संदीप सिंह, चंदन पटेल, प्रियांशु संजू यादव) ने रोगियों की जांच की। इस अवसर पर संस्थाध्यक्ष सीए राजेश राज गुप्ता ने लोगों का स्वागत करते हुए बताया कि अन्धत्व निवारण कार्यक्रम के तहत जौनपुर क्षेत्र को मोतियाबिंद मुक्त बनाने के उद्देश्य से ये शिविर लगाया गया। संयोजक डॉ संदीप मौर्य ने बताया कि ऑपरेशन के लिए वाराणसी भेजे गए रोगियों के भोजन, आवास और परिवहन की सुविधा निशुल्क रहेगी। उन्हें निशुल्क दवाइयां और चश्मे भी प्रदान किए जाएंगे। आपरेशन के बाद तीसरे दिन मरीज को इसी कैंप स्थल पर छोड़ दिया जायेगा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।